पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2012 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 21575

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1424

==

बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय, पटना जोन, आर-ब्लॉक, पहली मंजिल, चाणक्य टावर, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना, बिहार, 812005।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. भारत संघ नई दिल्ली
2. केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1, धनबाद संख्या 1, धनबाद के माध्यम से भारत संघ
3. श्री राजेश कुमार, पिता- श्री रामशीष पांडे, निवासी- गाँव- बभानी, पोस्ट ऑफिस- लहथुआ, थाना- मोहनपुर, जिला- गया

.... उत्तरदातागण/ओं

==

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए:	श्री अजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
	श्री अजीत कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
	सुश्री दिलकाश खान, अधिवक्ता
भारत संघ के अधिवक्ता:	श्री सत्येंद्र कुमार झा, सी.जी.सी
उत्तरदाताओं के लिए:	श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

==

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट---खण्ड 10---भारत का संविधान---अनुच्छेद 227---- औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखने वाले विद्वान रिट न्यायालय के निर्णय को चुनौती, जिसने तीसरे प्रतिवादी, रिट याचिकाकर्ता-बैंक के एक कर्मचारी को निधियों के दुरुपयोग के आरोप पर दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को रद्द कर दिया था---निष्कर्ष: जब अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही के अनुसरण में दी गई सजा न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाती है; जांच की प्रभावोत्पादकता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाए जाने पर, न्यायाधिकरण को पहले उस पर विचार करना होता है---यदि किसी कारण से जांच में त्रुटि पाई जाती है, तो प्रबंधन आरोपों को साबित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है--- ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि बैंक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाहों की सूची या दस्तावेजों की सूची दाखिल करके साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था--- न्यायाधिकरण ने यह देखा कि उसके समक्ष कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी उसने घरेलू जांच में साक्ष्यों का अध्ययन किया और पाया कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं; शिकायतकर्ताओं के बयानों पर भी भरोसा करते हुए--- चूंकि न्यायाधिकरण के प्रारंभिक आदेश, जिसमें जांच को त्रुटिपूर्ण पाया गया था, को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं है--- न्यायाधिकरण के प्रारंभिक आदेश को चुनौती न देने में बैंक की लापरवाही के कारण ही न्यायालय असहाय हो गया है--- न्यायाधिकरण का आदेश, जहां तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने और 50% पिछले वेतन के साथ पुनः नियुक्ति प्रदान करने का है, पुष्टि की गई--- अपील खारिज की जाती है। ***(पैरा- 1, 2, 8, 11-13)***

(1972) 1 एससीसी 595 ***.......को संदर्भित किया गया।***

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

कैव जजमेंट

द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश

दिनांक: 01-08-2024

यह रिट याचिका औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें तीसरे प्रतिवादी, जो रिट याचिकाकर्ता-बैंक का कर्मचारी था, को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को रद्द कर दिया गया था।

2. आरोप धन के दुरुपयोग का था, जिस पर बैंक ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी। जांच की गई, जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए और बैंक ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी थी।

3. विशिष्ट आरोप यह था कि याचिकाकर्ता, जो एक कैशियर था, ने 2 ग्राहकों से उनके खातों में जमा करने के लिए राशि प्राप्त की थी, जिसका न तो उनके खातों में भुगतान किया गया था और न ही यह बैंक के खाते में दिखाई दिया था। जब शिकायतें दर्ज की गईं तो याचिकाकर्ता ने राशि जमा कर दी।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि जांच में केवल बैंक के कर्मचारियों की जांच की गई थी और प्रबंधन की ओर से एम1 से एमई18 को चिह्नित किया गया था। जबकि कर्मचारी, तीसरे प्रतिवादी ने जांच अधिकारी के सामने 2 दस्तावेजों को चिह्नित किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि शिकायतकर्ताओं, यानी जिन ग्राहकों के पैसे के गबन के बारे में कहा गया था, की प्रबंधन द्वारा जांच नहीं की गई थी; जिसे न्यायाधिकरण ने दंड को रद्द करने में भी तवज्जो दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि शिकायतकर्ताओं से पूछताछ नहीं किए जाने के अलावा, यह सबूत के रूप में सामने आया है कि राशि शिकायतकर्ताओं के खातों में जमा की गई थी। शिकायतकर्ताओं ने शपथ पत्र भी दिया था कि उन्हें दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था। शिकायतकर्ताओं की गैर-जांच को महत्वपूर्ण पाते हुए, गबन को साबित नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजय कुमार सिन्हा और तीसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राकेश कुमार सिन्हा को सुना।

6. जाँच रिपोर्ट को देखने के बाद, हम आश्वस्त नहीं थे कि न्यायाधिकरण के आदेश या विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा जा सकता है; यदि हमें जाँच में निष्कर्षों के

अनुसार जाना है। शुरुआत में, हमें ध्यान देना होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए शिकायतकर्ताओं के 'हलफनामे' को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसे दिनांक 13.07.24 के पूरक हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया गया है। अनुलग्नक ए-4 और ए-5 के रूप में प्रस्तुत किए गए उक्त दस्तावेज शपथ पत्र के रूप में नहीं हैं और केवल पत्र हैं। शिकायतकर्ताओं में से एक ने कहा था कि उसने पैसे जमा नहीं किए थे और उसने गलती से इसे अपनी जेब में रख लिया था, जिसका बाद में शिकायत दर्ज होने के बाद पता चला। दूसरे शिकायतकर्ता ने पत्र में कहा है कि गलतफहमी के कारण शिकायत दर्ज की गई थी। इन दोनों दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लेखकों की जांच, जांच अधिकारी के समक्ष नहीं की गई थी और न ही यह शपथ पत्र के रूप में था, जिस पर उस व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे जो दस्तावेजों की शपथ लेने के लिए अधिकृत था; साक्षी की पहचान के बाद।

7. हम यह भी देखते हैं कि शिकायतों को जांच में प्रस्तुत किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उस तारीख को इंगित करता है जिस पर जमा किए गए थे; आगे दोषी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित काउंटरफॉइल द्वारा साबित किया गया। उपस्थिति रजिस्टर ने साबित किया कि दोषी कर्मचारी उक्त तिथियों पर बैंक में मौजूद था। बैंक में रखे गए खाता-बही ने काउंटरफॉइल के अनुसार राशि जमा करने का खुलासा नहीं किया और जमा बहुत बाद में किया गया था। जहाँ तक गबन का संबंध है, तो इस मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए था। हालांकि, हम अनुच्छेद 227 के तहत एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश पर विचार कर रहे हैं।

8. रिट याचिका में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत न्यायाधिकरण का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि दिनांक 25.05.12 के एक आदेश द्वारा, घरेलू जांच को निष्पक्ष और उचित नहीं माना गया था। प्रबंधन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 21.06.12 को मामला तय करते हुए नोटिस भेजा गया, जिसके विफल होने पर तर्कों की सुनवाई प्रस्तावित की गई। प्रबंधन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सामान्य सिद्धांत यह है कि जब किसी अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही के अनुसरण में दी गई सजा न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाती है, तो जांच की प्रभावकारिता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाए जाने पर न्यायाधिकरण को पहले उस पर विचार करना होता है। यदि जांच किसी भी कारण से दोषपूर्ण पाई जाती है, तो प्रबंधन आरोपों को साबित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

9. यहां **(1972) 1 एससीसी 595; दिल्ली क्लॉथ जनरल मिल्स कंपनी बनाम लुध बुध सिंह** का संदर्भ उपयुक्त होगा, जिसका पैराग्राफ 61 नीचे उद्धृत है:-

"(1) यदि प्रबंधन द्वारा कोई घरेलू जांच नहीं की गई थी, या यदि प्रबंधन यह स्पष्ट करता है कि वह अपने द्वारा की गई किसी भी घरेलू जांच पर भरोसा नहीं करता है, तो वह अपनी कार्रवाई को उचित ठहराते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष सीधे सबूत पेश करने का हकदार है। न्यायाधिकरण गुण-दोष के आधार पर अपने समक्ष प्रस्तुत उस साक्ष्य पर विचार करने और उस पर निर्णय देने के लिए बाध्य है। ऐसे मामले में, न्यायाधिकरण के लिए घरेलू जांच की वैधता पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि नियोक्ता स्वयं इस पर भरोसा नहीं करता है।

(2) यदि एक घरेलू जांच आयोजित की गई थी, तो प्रबंधन के लिए यह खुला है कि वह पहली बार में अपने द्वारा आयोजित घरेलू जांच पर भरोसा करे, और वैकल्पिक रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के कि जांच उचित और बाध्यकारी है, साथ ही साथ न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी कार्रवाई को उचित ठहराते हुए अतिरिक्त सबूत पेश करे। ऐसे मामले में, बिना किसी अतिरिक्त बात के यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रबंधन ने अपने द्वारा की गई जांच को छोड़ दिया है।

(3) जब प्रबंधन अपने द्वारा की गई जांच पर निर्भर करता है, और साथ ही न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है, तो उसकी याचिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि जांच की कार्यवाही उचित है, यह न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले इस बात पर विचार करे कि प्रबंधन द्वारा की गई जांच कार्यवाही वैध और उचित है या नहीं। यदि न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि जांच की कार्यवाही ठीक से आयोजित की गई है और वैध है, तो उसके समक्ष गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। यह तभी माना जाता है जब न्यायाधिकरण यह मानता है कि जांच की कार्यवाही ठीक से आयोजित नहीं की गई है, तो वह विवाद के गुण-दोषों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है और ऐसे मामले में उसे प्रबंधन द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करना होता है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर मामले का निर्णय करना होता है।

(4) जब प्रबंधन द्वारा एक घरेलू जांच आयोजित की गई है और प्रबंधन उसी पर निर्भर करता है, तो बाद वाला न्यायाधिकरण से अनुरोध करने के लिए खुला है कि वह प्रारंभिक मुद्दे के रूप में घरेलू जांच की वैधता का परीक्षण करे और न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी मांगे, यदि प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्ष प्रबंधन के खिलाफ है। प्रक्रिया चाहे कितनी भी विस्तृत और बोझिल क्यों न हो, ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के लिए यह स्वतंत्र है कि वह घरेलू जांच की वैधता को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में देखे। यदि प्रारंभिक मुद्दे पर इसका निष्कर्ष प्रबंधन के पक्ष में है, तो प्रबंधन को कोई अतिरिक्त सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्ष प्रबंधन के खिलाफ है, तो न्यायाधिकरण को नियोक्ता को अतिरिक्त साक्ष्य का हवाला देने का अवसर देना होगा और कर्मचारी को इसके विपरीत साक्ष्य देने का समान अवसर भी देना होगा, क्योंकि प्रबंधन द्वारा कार्यवाही के दौरान और मुकदमे के समाप्त होने से पहले न्यायाधिकरण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। जब प्रारंभिक मुद्दे पर प्रबंधन के खिलाफ निर्णय लिया जाता है और बाद में न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में स्थिति यह होगी कि प्रबंधन घरेलू न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को कथित कदाचार के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में स्वीकार किए जाने के लाभ से वंचित हो जाएगा। दूसरी ओर, प्रबंधन को उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना होगा कि कर्मचारी कदाचार का दोषी है और उसके द्वारा की गई कार्रवाई उचित है। प्रबंधन या कर्मचारी के लिए यह न्यायसंगत और निष्पक्ष नहीं होगा कि न्यायाधिकरण साक्ष्य लेने से इनकार करे और इस तरह प्रबंधन को उचित जांच करने के बाद आगे आवेदन करने के लिए कहे, और कामगार को स्वयं न्यायाधिकरण के लाभ से वंचित कर दे, क्योंकि न्यायाधिकरण स्वयं अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि वह कथित कदाचार का दोषी था या नहीं।

(5) प्रबंधन को न्यायाधिकरण के समक्ष स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने आदेश को बनाए रखने का प्रयास करने का अधिकार मिला है। लेकिन प्रबंधन को कार्यवाही बंद होने से पहले न्यायाधिकरण से एक उपयुक्त अनुरोध करके उक्त

अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि कार्यवाही बंद होने से पहले प्रबंधन द्वारा इस तरह के किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाया गया है या माँगा नहीं गया है, तो नियोक्ता कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि न्यायाधिकरण ने ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया है। न्यायाधिकरण के समक्ष केवल जांच की कार्यवाही होगी और उसे यह तय करना होगा कि क्या कार्यवाही ठीक से आयोजित की गई है और उसमें दर्ज किए गए निष्कर्ष भी उचित हैं।

(6) यदि नियोक्ता केवल घरेलू जांच पर निर्भर करता है और एक साथ अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व नहीं करता है या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए अवसर नहीं मांगता है, तो न्यायाधिकरण का कर्तव्य केवल घरेलू जांच की वैधता के साथ-साथ उसमें दर्ज निष्कर्ष पर विचार करना और मामले का निर्णय करना है। यदि न्यायाधिकरण यह निर्णय लेता है कि घरेलू जांच ठीक से नहीं की गई है, तो उसके द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराने के लिए उसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता को स्वतः आमंत्रित करना उसका कार्य नहीं है।

(7) उपरोक्त सिद्धांत न्यायाधिकरण के समक्ष, जो या तो धारा 10 के तहत एक संदर्भ पर या अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन के माध्यम से इसके समक्ष आया है।

(जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित)

10. प्रबंधन को अंतिम निर्णय पारित होने तक न्यायाधिकरण के प्रारंभिक निष्कर्ष को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पुरस्कार पारित होने के बाद, यदि यह प्रबंधन के खिलाफ है, तो प्रबंधन पुरस्कार के साथ-साथ प्रारंभिक आदेश को भी चुनौती दे सकता है। हम रिट याचिका में चुनौती दिए गए 25.05.12 के प्रारंभिक आदेश को नहीं पाते हैं।

11. प्रत्यर्थी-बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तब प्रस्तुत किया कि हालांकि बैंक के एक प्रतिनिधि ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी। हमारे द्वारा किए गए एक विशिष्ट प्रश्न पर, क्या ऐसा कोई तर्क लिया गया था, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष रूप से अनुच्छेद 17 की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि प्रबंधक आई.आर., जिसे उप-क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा

अधिकृत किया गया था, विधिवत अधिकृत नहीं पाया गया था क्योंकि प्राधिकरण क्षेत्रीय प्रबंधक से नहीं आया था, जो न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि बैंक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाहों की सूची या दस्तावेजों की सूची दाखिल करके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

12. न्यायाधिकरण ने इस बात पर ध्यान दिया कि घरेलू जांच में साक्ष्य के माध्यम से जाने से पहले कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया है और शिकायतकर्ताओं के बयानों पर भी भरोसा करते हुए आरोप साबित नहीं हुए हैं। हम जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर न्यायाधिकरण से सहमत नहीं हैं, लेकिन, हालांकि, उक्त रिपोर्ट को न्यायाधिकरण द्वारा प्रारंभिक आदेश द्वारा दोषपूर्ण के रूप में दरकिनार कर दिया गया था, जब कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो न्यायाधिकरण सजा के आदेश को दरकिनार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।

13. परिस्थितियों की समग्रता में, हालांकि हम विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क से सहमत नहीं हैं, हम न्यायाधिकरण के आदेश को परेशान करने का कोई कारण नहीं पाते हैं; क्योंकि प्रारंभिक आदेश में जांच को दोषपूर्ण पाया गया है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। यदि प्रारंभिक आदेश को हमारे सामने चुनौती दी गई थी और हमें उसमें कमजोरी मिली होती, तो हम अपराधी को दोषी या अन्यथा खोजने के लिए घरेलू जांच में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा कर सकते थे। न्यायाधिकरण के प्रारंभिक आदेश को चुनौती न देने में बैंक की लापरवाही के कारण न्यायालय असहाय हो गया है। इसलिए हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करने और 50% पिछले वेतन के साथ बहाली देने के न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हैं। यदि कोई पेंशन दी गई है, तो उसे बकाया के रूप में 50% पिछला वेतन देते समय काट लिया जाए।

14. याचिका खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्तिः मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

शारुन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।